

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

विषय : नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर जनपद ठिहरी गढ़वाल में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष-2005-06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर जनपद ठिहरी गढ़वाल में अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रस्तुत रु०-124.59 लाख की लागत के आगणन वित्तीय रु०१०५०८०० द्वारा परीक्षणोपरान्त रु०-115.05 लाख (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख पाँच हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय रवीकृति प्रदान हरी हुए इसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रु० 57.52 लाख (अर्थात् रूपये सत्तावन लाख बावन हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक द्वापट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता वित्ती राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जगा किया जायेगा, वित्ती भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व राजी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानवित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समरत औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राधिकृत स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य अपारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं रामयद्वता हेतु सम्बन्धित निर्माण एंजीनीरों के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

- 6- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तापुरितका, बजट गैनुअल, रटोर परचेज सल्ला एवं मित्रव्यिधिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुक्त प्राविधिक योग्यता आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य उत्तरान करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 7- कार्यदायी संस्था का निर्धारण शासनादेश रा० 452/XXVII(1)/2005 दि० ०५ अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 8- यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को 31-3-2006 तक समर्पित कर दी जायेगी।
- 9- कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ईओ० के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।
- 10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुक्त आहरण न करके यथाआवश्यकता हो किश्तों में आहरण किया जायेगा।
- 11- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था वो अग्रेस्टर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुक्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और उत्तीम किश्त तथा ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो। शासनादेश के मानकों को अनुरूप हो।
- 12- आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिकारी अग्रिमता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 13- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- 14- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि�०पि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करती समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- 15- विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो०नि�०पि० के अधिकारी अग्रिमता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समरत कार्य का रथल मिरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा करा लिया जायेगा एवं रथल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

स्वीकृत
अधिकारी

- 16— निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नगूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- 17— शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को एक वर्ष के भीतर उपलब्ध करा दिया जाये। और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किंशत अवमुक्त की जायेगी।
- 18— शासन द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि सी.सी.सड़कों के बजाय टाईल्स की सड़कों बनाई जायेंगी अतः उपरोक्त धनराशि व्यय करने से पूर्व टाईल्स सड़कों का पुनरीक्षित आगणन भी शासन को सहमति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय।
- 19— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष—2005–06 के आय-ब्याज के अनुदान सं0–13, लेखाशीष्टक—2217—शहरी विकास—03-छोटे तथा ग्राम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास—42 अन्य ब्यय के नामे डाला जायेगा।
- 20— यह आदेश वित्त विभाग के अराज0सं0–521 / XXVII(2) / 2006, दिनांक— 25 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/(अमरेन्द्र सिंह)
सचिव।

सं0 686(1) / V-श0वि0-06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेसितः—

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
 2— निजी सचिव, मा० नगर विकास मंत्री जी।
 3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 4— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
 5— वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
 6— निदेशक, एन0आई0सी०, संघिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
 7— अध्यक्ष/अधिकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर।
 8— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, संघिवालय परिसर, देहरादून।
 9— गार्ड बुक।

आज्ञा से

मायावती
(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

शासनादेशसं 686 / V-श0वि0-06-191(सा10) / 05, दिनांक 25 मार्च 06 का
संलग्नक

क्र०सं	कार्य का नाम	आगणनकी लागत (लाख अनुमोदित करो में)	टो०.एसी से अवगुप्त अनुमोदित (लाख रु० (लाख में))	पन्तराटे रु०
01	लो०नि०वि० सड़क से बक्कार के मकान तक नाला निर्माण	2.67	2.67	1.33
02	लो०नि०वि० सड़क से कोषागार एवं एस०री०इ०आ०टी० को जाने वाली सड़क की भरमत एवं रुक्का दिवार का निर्माण	11.34	10.62	5.31
03	लो०नि०वि० कार्यालय को जाने वाली सड़क से राजभाल तक सी०सी० सम्पर्क मार्ग एवं क्षतिग्रस्त दिवार का निर्माण	8.30	8.30	4.18
04	सन बू० हौटल से रेगमी भदन लो०नि०वि० रोड तक सी०सी० सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.78	2.06	1.33
05	नरेन्द्रनगर में स्वागत द्वार का निर्माण	2.69	2.40	1.20
06	बखरियाडा बरती को जाने वाले अदरेष मार्ग का निर्माण	6.56	6.14	3.37
07	फिनदानी में श्री जीत सिंह के मकान से श्री कुन्दन सिंह के मकान तक सी०सी० सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3.02	2.85	1.92
08	अपडा मैदान के सभीप सामुदायिक केन्द्र एवं शोपिं काम्प्लेक्स का निर्माण	14.65	13.70	8.85
09	नरेन्द्रनगर में आयुर्वेदिक विकित्सायल से आर्मी रोड एवं राजकीय बालिका इन्टर कलेज से सन बू० हौटल तक नाला निर्माण	25.31	25.30	12.65
10	नरेन्द्रनगर में रस्टार हाउस का निर्माण	5.57	5.35	2.67
11	नरेन्द्रनगर में बाईपास रोड से ठा० किशोर सिंह के मकान तक सी०सी० सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1.44	1.44	0.72
12	कुमारखेडा में श्री हरिवन्द के मकान से सुन्दरलाल के मकान होते हुए लो०नि०वि० कार्यालय तक सी०सी० रामपर्व मार्ग का निर्माण	3.29	2.88	1.44
13	लो०नि०वि० सड़क से रिहा हाउस एवं श्री सुरेन्द पुष्टीर के मकान तक सी०सी० सम्पर्क मार्ग का निर्माण	4.10	3.75	1.97
14	नरेन्द्रनगर में दूरभाष केन्द्र के सभीप छोडा स्थल का निर्माण	27.30	21.70	10.85
15	मुख्य बाजार नरेन्द्रनगर एवं कुमारखेडा में पिगिन री०सी० सम्पर्क मार्ग का निर्माण	5.51	5.23	2.63
	कुल योग-	124.59	115.05	57.52

(रूपये सत्तावन लाख बावन हजार मात्र)

मुक्त
संघर्षा दक्षिणात्मक
कानूनी सेवा
संस्था । १९८८
कानूनी सेवा